.....आखिर क्यों पिट रहा है हरियाणा

वाई. के. रज्जन

हरियाणा का मुख्यमंत्री तो बीफखाने वाले मुसलमानों को देश छोड़ने की सलाह दे रहा है लेकिन उनकी सरकारी पत्रिका में लेख छापा जा रहा है कि बीफसमेत कई और जानवरों का भी मांस बहुत पौष्टिक होता है, इनसे आयरन मिलता है। इनमें गाय के बछड़े से लेकर सुअर तक का मांस शामिल है। शिक्षा भारती नाम की जिस सरकारी पत्रिका ने यह लेख छापा था, उसकी संपादिका देवयानी सिंह को सरकार ने हटा दिया और शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा ने बयान दिया कि पत्रिका में जो कुछ छपा है, उसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस घटना ने यह पोल खोल दी कि यह सरकार किस तरह चल रही है और आगे हरियाणा का भविष्य राजनीतिक रूप से कितना अंधकारमय है। खास बात यह है कि पत्रिका छापने वाले संस्थान से मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री सीधे जुड़े होते हैं और वे अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते।

शिक्षा भारती पत्रिका हरियाणा शिक्षा विभाग की नीतियों, क्रिया-कलापों, ज्ञानवर्धक लेखों के लिए निकाली जाती है लेकिन सरकार ने इस पत्रिका की संपादक जिस देवयानी सिंह को बनाया था, वह हरियाणा के आईएएस विजेंद्र सिंह की पत्नी हैं। विजेंद्र सिंह हारट्रॉन के एमडी हैं। यह बात शीशे की तरह एकदम साफहै कि जिस पद पर किसी काबिल शिक्षाविद या पत्रकार को होना चाहिए, वहां एक आईएएस की पत्नी को बैठाकर उसे उपकृत करने की कोशिश है। हम देवयानी सिंह की काबिलियत यदि उनमें है, को कम नहीं आंक रहे हैं, यह बता रहे हैं कि उन्हें यह पद एक आईएएस की पत्नी होने के नाते ही मिला। लेकिन जिस चालाकी से हरियाणा सरकार ने उस विवादास्पद लेख का सारा ठीकरा उस बेचारी संपादिका पर फोड़ा है, वह भी कम नहीं निंदनीय है। वह एक तथ्यात्मक लेख था, जिसे सिर्फज्ञानवर्धन के लिए छापा गया। लेकिन क्या सरकार ने उस संपादक को अपनी नीतियों की जानकारी दी कि कभी भी जनता को यह भूले से नहीं बताना है कि बीफसेहत के लिए फायदेमंद चीज है।

बहरहाल, हरियाणा चंद नौकरशाहों और नेताओं की लूटखसोट का अड्डा बना हुआ है। इससे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में नौकरशाही ने जो लूटखसोट, खुद को फायदा पहुंचाने का जो धंधा चला रखा था, वह इस सरकार में भी बदस्तूर जारी है। जिसकी पुष्टि इस घटना से हुई है। हारट्रॉन नामक जिस सरकारी कॉरपोरेशन में देवयानी सिंह के पति विजेंद्र सिंह को बताया जा रहा है, जिसमें सरकार ने 6-7 आईएएस अफसरों को खपाया हुआ है। हारट्रॉन जिसका पूरा नाम हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड है, वह अफसरों की दलाली का एक और सेंटर है। अगर सरकार से पूछा जाए कि उसने हारट्रॉन से अब तक क्या तीर मारे हैं, तो उसके पास बताने के लिए न पहले कुछ था और न अब कुछ है। यह कॉरपोरेशन न तो किसी चीज का उत्पादन करता है और न ही इसने कोई कारखाना लगाया हुआ है। यह बाजार से इलेक्ट्रॉनिक्स सामान महंगे दाम पर खरीद कर सरकार के तमाम विभागों को ही महंगे दाम पर बेचती है।

यानी कमीशनबाजी की आड़ में जो रकम आती है, वह अफसरों में ईमानदारी से बराबर बांट दी जाती है। किसी सरकारी दफ्तर में कंप्यूटर लगने हैं तो वह हारट्रॉन से कहता है, हारट्रॉन उसे बाजार से खरीदकर दे देता है। इसने ट्रेनिंग सेंटर भी खोल रखे हैं। आईटी ;सूचना प्रौद्योगिकी सलाह देने का धंधा भी चला रखा है जिसमें कई स्त्रोतों से कमाई हो सके। यह समझ से परे है कि छोटे से हरियाणा प्रदेश में एक कॉरपोरेशन में 6-7 आईएएस क्यों खपाए गए हैं, जबकि पूरे कॉरपोरेशन की कोई जरूरत नहीं है।

दक्षिण पंथियों की जल्लादी मानसिकता

याकूब मेमन को फ़ांसी के सिलसिले में एक बार फ़िर यह देखने में आया कि दक्षिणपंथी सोच के लोग जल्लादी मानसिकता के होते हैं। वे बड़े अपराध के लिये अपराधियों को फ़ासी चढाने या मौत की सज़ा देने के पक्षधर होते हैं। वे आमतौर पर ही अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा देने के पक्ष में होते हैं। उनके अनुसार इसी से अपराधों को रोका जा सकता है और समाज को सुरक्षित बनाया जा सकता है।

दक्षिणपंथी सोच की यह परिघटना वैश्विक है भारत के दक्षिणपंथी कोई अपवाद नहीं हैं। वे एक सामान्य प्रवृत्ति को प्रकट करते हैं।

एक राजनीतिक सोच के तौर पर दक्षिणपंथी वे लोग होते हैं जो समाज में कोई आगे की ओर बदलाव नहीं चाहते। वे या तो यथास्थिति के हामी होते हैं या फ़िर यदि वे कोई बदलाव चाहते हैं तो पुराने समाज की ओर या पीछे की ओर। खासकर धार्मिक कट्टरवाले दक्षिणपंथी पुराने सामंती जमाने की ओर जाना चाहते हैं। जब उनके अनुसार उनके धार्मिक समाज का स्वर्ण युग था। यह भाजपा किस्म के संघी दक्षिणपंथियों के लिए भी सच है जो मध्यकालीन सामंती हिन्दू समाज-सनातन धर्म को अपना आदर्श मानते हैं।

इन धार्मिक दक्षिणपंथियों के लिए उनके मध्यकालीन सामंती धर्म को छोड़कर समाज केवल बिगड़ा ही है। वे इस परिवर्तन को पानी पी-पी कर कोसते हैं। और जब प्रगतिशील लोग सार्वजनिक जीवन में धर्म की रही-सही भूमिका को भी खत्म करने की मांग करते हैं तब इन्हें लगता है कि प्रलय आ जायेगी। उनकी इच्छा वर्तमान समाज को सामंती युग में वापस ले जाने की होती है।

सामंती जमाने में न्याय की धारणा एकदम सीधी थी-धन के बदले धन, अंग के बदले अंग और जान के बदले जान। लेकिन इसमें सामंती जमाने के अनुसार सज़ा का पैमाना भी बदलता है। ब्राह्मण और शूद्र के लिये एक ही अपराध के लिये सज़ा के अलग-अलग प्रावधान थे।

सामंती जमाने के इस न्याय में अपराधी के भविष्य में सुधर जाने की कोई धारणा नहीं थी। इसलिए कैद केवल राजा के शत्रुओं के लिए ही थी। इसीलिए बाकी अपराधी सज़ा पाकर मुक्त हो जाते थे-कुछ तो दुनिया से ही। स्वभावत: इन सबमें अपराध के लिए व्यक्ति को ही जिम्मेदार माना जाता था।

इस तरह धार्मिक कट्टरपंथी सोच वाले दक्षिणपंथी अपनी समग्र सामंती सोच के कारण ही अपराध और अपराधियों के मामले में जल्लादी मानसिकता के होते हैं। और जब समाज की प्रगति उनकी सोच पर लगातार प्रहार करती है तो वे बिलबिला उठते हैं। वे और ज़्यादा प्रतिशोधी हो जाते हैं। इस तरह के धार्मिक कट्टरपंथी दक्षिणपंथी आज के धर्मनिरपेक्ष दक्षिणपंथियों से घुल-मिल गये हैं। इसका भी कारण है। दक्षिणपंथी आज के सड़े-गले पूंजीवादी समाज को बचाना चाहते हैं। वे इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। इसी कारण उन्हें धार्मिक कट्टरपंथ को प्रोत्साहन देने में भी कोई परेशानी नहीं है। साम्राज्यवादी पूंजीपति जहां सारी दुनिया में धार्मिक कट्टरपंथियों को पाल-पोस रहे हैं और प्रश्रय दे रहे हैं वहीं अपने देश में भी।

दक्षिणपंथी अपनी पतित व्यवस्था को बचाना चाहते हैं। वे उसके ख़िलाफ़ उठने वाली आवाज़ को दबाना चाहते हैं। वे इसे वैचारिक तौर पर भी करते हैं और भौतिक तौर पर भी।

वे व्यवस्था के खिलाफ़ सीधे खड़े होने वाले लोगों को देशद्रोही, राजद्रोही या आतंकवादी कहकर उसका दमन करते हैं। वे व्यवस्था से परेशान लोगों या व्यवस्था से पैदा हो रही विकृतियों के शिकार लोगों यानी आम अपराधियों का भी दमन करते हैं। हालांकि दोनों प्रकार के अपराधों के लिए अलग-अलग बात करते हैं पर अंतत: उनका तर्क व्यक्ति पर केन्द्रित हो जाता है। वे बताते हैं कि अपराध के लिए व्यक्ति ही जिम्मेदार है।

अपराध के लिए ऐसा तर्क दक्षिणपंथी की मजबूरी है। यदि अपराध के लिए व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहराया जो इसका केवल एक मतलब निकलता है-अपराध के लिए समाज या सामाजिक व्यवस्था जिम्मेदार है। और यदि अपराध के लिए सामाजिक व्यवस्था जिम्मेदार है तो अपराध तभी समाप्त हो सकते हैं जब सामाजिक व्यवस्था को बदला जाये। दक्षिणपंथी इसे कभी नहीं स्वीकार कर सकते क्योंकि वे दक्षिणपंथी होते इसलिए हैं कि यथास्थितिवादी होते हैं। वे व्यवस्था में आगे की ओर बदलाव के विरोधी होते हैं।

इस तरह जल्लादी मानसिकता दक्षिणपंथियों के खून में होती है जो संगीन मौके पर अपना नंगा नाच करने लगती है।

दक्षिणपंथियों के ठीक विपरीत वामपंथियों को अपराध के लिए सबसे पहले वर्तमान व्यवस्था को कठघरे में खड़ा करना चाहिए।

'स्मार्ट सीटी' में अवैध निर्माणों का धंधा

फ़रीदाबाद (म.मो.) एन.एच.5 नम्बर मेन मार्किट शिव मंदिर रोड पर स्थित एसएसआई प्लॉट नम्बर-6 में नगर निगम के तोड़-फ़ोड़ दस्ते द्वारा गत वर्ष इस पलॉट में बन रही अवैध शॉपिंग काम्पलैक्स में तोड़-फ़ोड की गई थी। अवैध दुकान को सील किया गया था जिसके बाद 2014 में शॉपिंग काम्पलैक्स के मालिक ने कोर्ट से स्टे ले लिया था कि जिस अवस्था में काम्पलैक्स है उसी अवस्था में रहेगी। इसमें कोई निर्माण नहीं किया जायेगा।

नगर निगम ने जनवरी 2014 में इस काम्पलैक्स का नक्शा पास किया था व अगस्त 2014 में नक्शा कैंसिल कर दिया था। लेकिन पार्षद पति नरेश गोसाई ने तत्कालीन नगर निगम के उच्च अधिकारियों को लग-भग 50 लाख रुपये की एक मोटी रकम दिलवा कर मामला रफ़ा-दफ़ा करवा दिया था। शॉपिंग काम्पलैक्स तैयार करवा दिया। ग्राऊंड फ़्लोर पर लगभग 30 दुकाने तैयार करवा दी जिसमें 15 दुकाने बिक कर आबाद भी हो गई जिनकी करीब 6 करोड़ में खरीद-फ़रोत हुई।

लगभग एक वर्ष बाद दिनांक 21/10/15 को इस काम्प्लैक्स के फ़र्स्ट फ़्लोर पर दोबारा निर्माण कार्य शुरू हो गया। नगर निगम ने पहले नक्शा पास किया, फ़िर कैंसिल किया। सवाल ये खड़ा होता है कि इस शॉपिंग काम्पलैक्स के मालिक पर सीलिम के बाद भी निर्माण करने का मामला क्यों नहीं दर्ज किया, जबकि इस काम्पलैक्स का सीएलयू भी नहीं हुआ न ही पार्किंग की व्यवस्था की गई। पहले ग्राऊंड फ्लोर की दलाली पार्षद पति नरेश गौसाई ने लेकर अवैध निर्माण करवाया था।

सुत्रों अनुसार फ़र्स्ट फ़्लोर व सेकेंड फ़्लोर को बनाने का ज़िम्मा एक मौजूदा प्रभावशाली राजनेता ने लिया है। क्योंकि इस काम्पलैक्स का मालिक अमरजीत चावला का उस नेता से गहरा याराना बताया जाता है। इसके बदले एक मोटी रकम के साथ-साथ पूरे सौदे में कुछ पार्टनरशिप की डील भी हुई है।

विदित है कि पिछले वर्ष इसी अवैध निर्माण की खबर भी 'मज़दूर मोर्चा' ने प्रकाशित की थी जिसके तुरंत बाद फ़र्स्ट फ़्लोर का निर्माण कार्य रूकबा दिया गया था।

सुत्रों अनुसार इस दलाली में कई पत्रकारों को भी रुपये बांटे गए थे। वही दूसरी तरफ़ नरेश गोसाई ने 5सी/44 में बने अवैध शॉपिंग काम्पलैक्स में भी साढे सात लाख रुपये लेकर 44 दुकाने तैयार करवा दी थी।

तुर्की-ब-तुर्की / अगर पहले मुआवजा दे दें तो मरने की जरूरत नहीं

''मैं विदर्भ के किसानों से अपील करता हूं कि वे अभी एक-दो महीने आत्महत्या से रूक जायें। सरकार इस विषय में कदम उठा रही है।''-मुख्यमंत्री महाराष्ट्र देवेन्द्र फ़ड़नवीस।

हमारा कहना है-

मुख्यमंत्री जी क्या इन एक-दो महीनों में आप पुन: विदेश यात्राओं पर निकलने वाले हैं ? जहां से आप किसानों की समृद्धि के लिये रामबाण दवा लायेंगे जिससे उन्हें आत्महत्या करने की नौबत न आये। सच्चाई तो यह कि किसान को आप जैसे राजनीतिबाज़ों के वायदों पर कोई भरोसा नहीं रहा। लिहाज़ा तंग आकर और कोई राह न पाकर ही वह आत्महत्या की ओर बढता है। स्थिति इतनी निराशजनक है कि अब तो किसानों के बच्चों ने भी आत्महत्या करनी शुरू कर दी है। लड़कियों की शिक्षा और शादी के लाले पड़ गये हैं।

आप जैसी सरकारें फ़ड़नवीस जी एक काम तो कर सकती हैं। उन किसानों की लिस्ट बना ली जाय जो आत्महत्या के कगार पर पहुंच चुके हैं। बैंक और महाजन के खातों से आपके शासन-प्रशासन को यह आसानी से पता लग सकता है। जिस पर जितना कठिन कर्ज लगा है वह आत्महत्या के उतना ही करीब है। यदि आप कोई ऐसी स्कीम बना सकें जिसके अन्तर्गत ऐसे व्यक्तियों को आधा मुआवज़ा आत्महत्या करने से पहले दिया जा सके तो आत्महत्या भी नहीं होगी और सरकार का पैसा भी बच जायेगा। आपके राज्य पर सर्वाधिक आत्महत्याओं का जो कलंक है वह भी दूर हो जायेगा।

आपके आका नरेन्द्र मोदी को इस तरह की योजनायें बहुत पसंद आती हैं। हो सकता है आपकी इस पहल से खुश होकर वह आपको अपने साथ विदेश यात्राओं पर ले जाने लगें। ऐसे में आप और ज़ोर-शोर से दावा कर पायेंगे कि अपने किसानों की आत्महत्या का हल ढूंढने को लेकर आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। खुदा न खास्ता कल आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटना पड़े तो केन्द्र में कृषि मन्त्री की कुर्सी तो पक्की ही समझो।

चुनाव करीब आ जायें तो आप अपनी मुआवज़ा स्कीम को और व्यापक कर सकते हैं। यानी, जैसे ही किसान के घर बच्चा जन्म ले उसके जन-धन बैंक खाते में आत्महत्या मुआवजे के पैसे डाल दिये जायें। आत्महत्या न करने तक वह आधे पैसे निकालने का हक़दार रहेगा। आत्महत्या करने के बाद उसे पूरे पैसे निकालने की छूट होगी। दोनों हालत में आपके वोट तो पक्के हो गये। इसमें चुनाव आयोग भी टांग नही अड़ा सकता।